भारत की G20 अध्यक्षता और वैश्विक खाद्य समस्या तथा प्राथमिक स्वास्थ्य का समाधान

विकास कुमार[1] एवं सुरेश पाल[2]

पंचायत प्रणाली का लाभ उठाते हुए, भारत ने सफलतापूर्वक सुदृढ़ और टिकाऊ सामुदायिक संस्थानों का निर्माण किया है जिन्होंने ग्रामीण लोगों की अपने विकास का प्रबंधन करने की क्षमता को सशक्त किया है। ये अनुभव उन देशों के लिए एक प्रेरणा हैं जो खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

हैदराबाद में कृषि पर जी20 मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए इकट्ठा होते हुए वैश्विक नेताओं के सामने चुनौतियां स्पष्ट होती प्रतीत हुईं। पिछले कुछ वर्षों में, हम संकट की तरफ बढ़े हैं जिससे सतत विकास लक्ष्यों पर वैश्विक प्रगति में गंभीर बाधा आई है। इसे संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 2015 में स्वीकार भी किया गया है। आज भले ही हम 10 अरब लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन पैदा करते हैं परंतु, गत दशकों में पहली बार खाद्य असुरक्षा से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती दिखाई पड़ रही है। आज, 800 मिलियन से अधिक लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। उनमें से कई, विरोधाभासी रूप से, छोटे पैमाने के किसान हैं जो दुनिया के एक तिहाई भोजन का उत्पादन करते हैं।

कुछ मामलों में खाद्य असुरक्षा की समस्या ग्रामीण है। दुनिया के सबसे गरीब और असुरक्षित जनसंख्या का तीन-चौथाई ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं, विशेष रूप से कृषि, पुरानी अल्प-

[1] भाकृअनुप- राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान, दिल्ली
[2] कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल

निवेश से पीड़ित हैं। आज, कम और मध्यम आय वाले देशों में ऋण की मात्रा बढ़ रही है और वैश्विक मुद्रास्फीति और स्थानीय मुद्रा मूल्यह्रास उनके लिए अपने विकास और जलवायु संबंधी कार्रवाई को वित्तपोषित करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, कृषि के लिए दाता सहायता कम से कम दो दशकों से कुल आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के 4-6 प्रतिशत पर स्थिर हो गई है। वर्ष 2020 में 10.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चरम पर पहुंचने के बाद, यह 2021 में 10 प्रतिशत से घटकर 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अनुमान बताते हैं कि खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए हमें 2030 तक सालाना 300-400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। इसलिए निवेश को कम से कम 30 बार बढ़ाने की जरूरत है।

ग्रामीण कृषि में निवेश करना सरकारों और कंपनियों दोनों के लिए आवश्यक है। सरकारों के लिए, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने, स्थानीय खाद्य श्रृंखलाओं और स्थानीय बाजारों को बढ़ावा देने का तात्पर्य है वैश्विक खाद्य सुरक्षा, नौकरी और कम संघर्ष की दिशा में बढ़ना। इसका तात्पर्य यह भी होगा कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा कृषि कुल उत्सर्जन के 21 प्रतिशत तक के लिए जिम्मेदार है। निजी क्षेत्र के लिए, छोटे पैमाने के किसानों में निवेश करना लाभदाई होती है। इसमें उत्पादन लागत कम है, पूंजी पर प्रतिफल अधिक है, किसान संगठनों और सहकारी समितियों ने दिखाया है कि वे बेहतर अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और फसल विविधीकरण से खेतों और बाजारों के लिए जोखिम को कम किया जा सकता है।

भारत में भूख विरोधाभास

वास्तव में देखा जाए तो उत्पादन में आत्मनिर्भरता का अर्थ खाद्य सुरक्षा नहीं है। इस दिशा में निवेश दीर्घकालिक अनुकूलन का निर्माण कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन और अन्य झटकों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अनुकूलन पर खर्च किया गया प्रत्येक यूएस $ 1 भविष्य में आपातकालीन सहायता में यूएस $10 तक बचाता है। अन्य क्षेत्रों में निवेश करने की तुलना में गरीबी को कम करने में कृषि में निवेश कम से कम 2-3 गुना अधिक प्रभावी है।

फिर भी छोटे पैमाने की कृषि को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। छोटे पैमाने के उत्पादकों के पास अभी भी ऋण, बाजार, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, जानकारी और भूमि तक पहुंच की कमी है। यह वह जगह है जहां बहुपक्षीय विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान एक बड़ा अंतर बना सकते हैं। यदि हम नवीन वित्तीय साधनों और तंत्रों के माध्यम से निवेश को जोखिम में डालते हैं, तो हम कृषि को विकास का केंद्र बनने में मदद कर सकते हैं, जिसमें इसकी क्षमता है।

भारत का जी20 प्रेसीडेंसी संसाधनों को जुटाने में वृहत महत्व रखता है जो हमें अंतार्राष्ट्रीय समुदाय के संकल्प को पूरा करने की अनुमति देगा ताकि

यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सस्ती, सुरक्षित, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन तक पहुंच हो। हम डिजिटलीकरण बढ़ाने, किसानों और बीमाकर्ताओं के लिए बीमा को आकर्षक बनाने, आसान और रियायती ऋण तक पहुंच प्रदान करने, भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने और किसान संगठनों को मजबूत करके ऐसा कर सकते हैं।

भारत ग्रामीण गरीबी और भूख को समाप्त करने के मिशन में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। पंचायत प्रणाली का लाभ उठाते हुए, भारत ने सफलतापूर्वक मजबूत सामुदायिक संस्थानों का निर्माण किया है जिन्होंने लोगों के अपने विकास का प्रबंधन करने की क्षमता को मजबूत किया है। ये अनुभव उन देशों के लिए प्रेरणा हैं जो खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत ने दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग को आगे बढ़ाने में विचारशील नेतृत्व दिखाया है। यह केवल अपने बढ़ते आर्थिक भार के साथ गहरा हो गया है।

"मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, ""भोजन, उर्वरकों और चिकित्सा उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति, ताकि भू-राजनीतिक तनाव मानवीय संकट का कारण न बनें ""का विरोध करने की भारतीय अध्यक्षता की प्रतिबद्धता का स्वागत करता हूं। " हम अधिक टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के निर्माण द्वारा दीर्घावधि से विद्यमान भूख और खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए जी20 की ओर देख रहे है। जी20 हमें मध्यम अवधि के स्थायी ग्रामीण विकास और कृषि में निवेश करने के लिए सरकारों, वैश्विक वित्तीय संस्थानों, निवेशकों और कंपनियों से प्रतिबद्धताओं को जुटाने के लिए बहुत आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यह उम्मीद है कि भारतीय अध्यक्षता समावेशी, लचीला और स्थायी खाद्य प्रणालियों के लिए परिचालन रूप में व्यावहारिक रोडमैप प्रदान कर सकता है। इससे 800 मिलियन लोगों के लिए खाद्य असुरक्षा की समस्या समाप्त हो जाएगी। इससे कुल 120 मिलियन से अधिक सुनियोजित ग्रामीण रोजगार पैदा होंगे, अंतिम 20 प्रतिशत आबादी के लिए आय को बढ़ावा मिलेगा, और जैव विविधता की रक्षा करते हुए जलवायु परिवर्तन का समाधान प्राप्त किया जा सकेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य का सुदृढीकरण

कोविड महामारी के प्रति सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्य और इस अवधि के दौरान किए गए नवोन्मेषों से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सशक्त और वृहत रूप देने की सबक प्राप्त हो रही है। भारत का जी20 प्रेसीडेंसी गति पकड़ रहा है। यह विश्व को महामारी से सुरक्षित बनाने के लिए साझा जिम्मेदारियों और कई देशों के सहयोग पर केंद्रित है। भारत वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच की खाई को पाटने के लिए इस मंच का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, खासकर क्योंकि जी20 और कई अन्य बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में सभी वैश्विक समुदाय की सदस्यता दिखाई नहीं पड़ती है।

कोविड–19 महामारी ने पुष्टि की है कि स्वास्थ्य एक वैश्विक सार्वजनिक भलाई है। इसने सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टि को आकार देने और इसे प्रदान करने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया है, खासकर क्योंकि बाजार की ताकतें अक्सर लोगों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती हैं। विशेष रूप से सबसे गरीब और सबसे कमजोर के लिए स्वास्थ्य हेतु विशेष आवश्यकता होती है। महामारी ने रोग के प्रकोप की गंभीरता की रूपरेखा को आकार देने में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की केंद्रीय भूमिका को भी विश्व के समक्ष खड़ा किया है।

इस प्रक्रिया में तैयार किया गया खाका राष्ट्रीय सरकारों और जी20 जैसे बहुपक्षीय संस्थानों पर लागू हो सकता है। इसके महत्वपूर्ण तत्वों में देशों को तुरंत प्रतिक्रिया देना, सटीक जानकारी प्रदान करना, महत्वपूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों तक पहुंचना, प्रशिक्षण और चिकित्सा पेशेवरों को जुटाना, टीके, जांच और चिकित्सीय सुविधा विकसित करना तथा वितरित करने में मदद करना आदि शामिल है। भारत ने कोविड से निपटने में संपूर्ण समाज और संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है। पहली और दूसरी विनाशकारी लहरों ने राष्ट्रीय एकजुटता को तेज कर दिया और चिकित्सा देखभाल और वैक्सीन अनुसंधान, उत्पादन और रोलआउट पर ध्यान केंद्रित किया गया। कोविड एक स्वास्थ्य आपातकाल से कम विषाक्त रूप में एक ऐसी बीमारी में बदलने के साथ, जो हमारे साथ होने की संभावना है अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं को पुनर्जीवित करने और फिर से बनाने के साथ–साथ लंबे समय तक पीड़ित लोगों की देखभाल करने के लिए स्थानांतरित हो गया है और पूरी तरह से कोविड और गैर–कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

महामारी के एक साल बाद, विश्व बैंक ने कुछ देशों और क्षेत्रों को लोगों पर महामारियों के प्रभाव को तैयार, रोकने, और कम करने के लिए अपनी क्षमताओं में सुधार करने में मदद करने के लिए एक छत्र कार्यक्रम की स्थापना की। भारत और जी20 और ग्लोबल साउथ के कई अन्य सदस्य इस प्रयास का हिस्सा हैं।

जनवरी 2022 में, डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड ने 150वीं बैठक में स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी और इसकी संरचना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र संक्रमण के खतरों से निपटने से आगे बढ़ गया है और एक सर्व–खतरे के दृष्टिकोण से भी आगे निकाल चुका है। ऐसी आपात स्थितियों के प्रबंधन के मुख्य मूल्यों में पहुंच और परिणामों में समानता स्वामित्व और जुड़ाव की समावेशिता, वित्तपोषण, शास और संवैधानिक जनादे में सामंजस्य शामिल है। इसलिए, मूलभूत आवश्यकताओं में अंतर–क्षेत्रीय समन्वय (आर्थिक, सामाजिक, कृषि, पर्यावरणीय) और संपूर्ण सरकारी और संपूर्ण समाज प्रतिक्रियाओं के साथ एक स्वास्थ्य "दृष्टिकोण शामिल है।

एक बढ़ती हुई चिंता है कि ठोस परिचालन कदमों की कमी और अपर्याप्त सार्वजनिक वित्तपोषण के कारण 2030 तक दुनिया सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) की अपनी सही दिशा में नहीं है। कोविड महामारी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया और इस अवधि के दौरान आए नवोन्मेषों जैसे डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों और समुदाय-आधारित सेवाओं से अनुभव लेते हुए यूएचसी की प्रगतिशील प्राप्ति के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत नवाचार और सहयोग के माध्यम से मील के पत्थर को प्राप्त करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है, विशेष रूप से चार सडीजी जैसे निर्धनता को समाप्त करना, पूरी खाद्य सुरक्षा , अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण एवं लिंग समानता।

स्वास्थ्य आपातकाल के रोडमैप के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना आवश्यक है। भारत का G20 प्रेसीडेंसी सुरक्षित और न्यायसंगत दुनिया के लिए WHO के 10 बोल्ड प्रस्ताव के साथ तालमेल की सुविधा प्रदान करेगा। एचईपीपीआर के प्रभावी और समय पर मजबूत होने के लिए हितधारकों के बीच समझौते और अभिसरण को गहरा करने की आवश्यकता होगी। भारत के G20 प्रेसीडेंसी का विषय-एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य – उस भावना का परिचय देती है।

एचईपीआर के तीन स्तंभ शासन, सहयोग और वित्तपोषण हैं। जिसमें भारत ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं और वैश्विक स्वास्थ्य शासन को मजबूत करने पर हाल की कुछ पहलों में राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है – इनमें महामारी संधि के लिए इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी (आईएनबी) , ओमान में एएमआर पर मस्कट मैनिफेस्टो (2022) , और दक्षिण अफ्रीका में मेडिकल काउंटर उपायों के मंच के मित्र (2023) प्रमुख। पांच परस्पर जुड़े बहु-क्षेत्रीय एचईपीआर प्रणालियों की परिचालन तैयारी – सहयोगी निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, सुरक्षित और स्केलेबल देखभाल, प्रतिउपायों तक पहुंच और आपातकालीन समन्वय – एक और प्राथमिकता वाला क्षेत्र है जिस पर भारत का जी20 प्रेसीडेंसी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

जी20 ने पहले ही डब्ल्यूएचओ और विश्व बैंक महामारी कोष में योगदान दिया है जिसे नवंबर 2022 में इंडोनेशिया प्रेसीडेंसी के दौरान शुभारंभ किया गया था। फंड ने ज्यादातर जी20 सदस्यों से 1.6 बिलियन डॉलर से अधिक दान प्राप्त किया है, जो वैश्विक दक्षिण के कई देशों में एचईपीआर को सुदृढ़ करेगा।